IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 9, Issue 1, September 2019
Impact Factor: 4.819

उपनिवेशवाद से गणतंत्र तक: स्वाधीनता संग्राम (1857-1947) में जन-भागीदारी और सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक विमर्श

डॉ. रजत गंगवार
असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बीसलपुर, पीलीभीत।
rajatgangwar4289@gmail.com

सारांश : भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक प्रक्रिया है जिसने उपनिवेशवादी शोषण के विरुद्ध करोड़ों भारतीयों को एक साझा राष्ट्रीय चेतना के सूत्र में बांधा। सन् 1857 के महान विद्रोह से लेकर 1947 में स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना तक की नब्बे वर्षों की यात्रा में जन-भागीदारी का स्वरूप निरंतर विस्तृत होता गया — यह संघर्ष प्रारंभ में सीमित वर्गों, विशेषकर सामंतों, सैनिकों और स्थानीय शासकों तक सीमित था, परंतु बीसवीं शताब्दी आते-आते यह किसानों, मजदूरों, महिलाओं, विद्यार्थियों और आदिवासी समुदायों तक फैलकर एक सच्चे जन-आंदोलन का रूप ले चुका था। प्रस्तुत शोध पत्र में इस संक्रमण की ऐतिहासिक पड़ताल करते हुए यह विश्लेषित किया गया है कि किस प्रकार सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक चेतना ने मिलकर एक संगठित राष्ट्रीय विमर्श को जन्म दिया? सारगर्भित ऐतिहासिक उदाहरणों — चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन तथा आदिवासी व किसान विद्रोहों — के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि स्वाधीनता संग्राम बहुस्तरीय, बहुवर्गीय और बहुक्षेत्रीय आंदोलन था, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने औपनिवेशिक दासता से मुक्त होकर एक लोकतांत्रिक गणराज्य का स्वरूप ग्रहण किया।

कुंजी शब्द- स्वाधीनता, उपनिवेशवादी शासन, राष्ट्रीय चेतना, जन भागीदारी, सत्याग्रह, औपनिवेशिक दासता, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक शोषण, क्रांतिकारी आंदोलन, जन जागरूकता, स्वदेशी, जनभागीदारी, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक दासता, श्रमिक वर्ग, राष्ट्रीय आंदोलन, अहिंसक प्रतिरोध, संगठित नेतृत्व, आर्थिक शोषण,धन निष्कासन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय।